

माननीय सुश्री हिमा कोहली, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की अध्यक्षता में 28 नवंबर, 2020 को प्रातः 11.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग(Cisco Webex) के माध्यम से हुई बैठक के कार्यवृत्त

बैठक में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्चाधिकार समिति के निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लिया:

1. श्री बी.एस.भल्ला, प्रमुख सचिव, (गृह)/अतिरिक्त मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार.....सदस्य
2. श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल), दिल्ली.....सदस्य।
3. श्री कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DSLSA)

एजेंडा: भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Suo Motu Petition (Civil) No. 1/2020–In Re: Contagion of COVID-19** दिनांक 23.03.2020 और 13.04.2020 में जारी किए गए निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन

आइटम न. 1: पहले अपनाए गए निर्णयों के आधार पर कैदियों की सुरक्षा, स्क्रीनिंग, पहचान, एवं कैदियों तथा जेल स्टॉफ के उपचार का जायजा

आरंभ में श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि समिति की पहले की बैठकों में लिए गए निर्णयों और दिशा निर्देशों तथा हिदायतों का पालन करने का जेल प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा सम्मिलित प्रयास किए गए। उन्होंने आगे सूचित किया कि पहले अपनाए गए निर्णयों का गहनतापूर्वक पालन करने के परिणामस्वरूप वे जेल परिसर के अंदर कोविड-19 (नोवेल कोरोना वायरस) के सक्रिय केसों को कम करने में सफल रहे हैं जबकि वर्तमान में दिल्ली में कोविड-19 के केसों में तेजी से वृद्धि हो रही है।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि उनके पत्र संख्या **No.PS/ DG(P)/2020/2089** दिनांक 27.11.2020 के द्वारा दिनांक 27.11.2020 तक दिल्ली जेल में कोविड-19 के सक्रिय केसों का संचयी आंकड़ा इस प्रकार है:

जेल में बंद कैदी : 114 ( 111 ठीक हुए, 02 की मृत्यु, 01 सक्रिय,

जेल स्टॉफ: 279 ( 263 ठीक हुए, 16 सक्रिय मामले)

कोविड-19 के एक सक्रिय केस के विषय में पूछे जाने पर महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि मंडोली की जेल सं. 16 में महिला कैदी का एक अव्यस्क बच्ची पाजिटिव

पायी गई थी। उसे उसकी मां के साथ GTB अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जहां उसे स्वास्थ्य लाभ हो रहा है।

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि दिनांक 20.06.2020 की तथा उसके पश्चात की बैठकों में लिए गए निर्णयों के आधार पर जेल प्रशासन 55 वर्ष से अधिक उम्र के कैदियों के संबंध में अधिक सावधानी बरत रहा है जिससे वे प्रतिरक्षा में अक्षम न हो पाएं। महानिदेशक (जेल) ने समिति को आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही जारी रखेंगे।

समिति के सदस्यों ने उन सभी संभावित तरीकों के विषय में विचार विमर्श किया जिससे कि कोविड-19 (नोवेल कोरोना वायरस) जेल परिसर में प्रवेश कर सकता है। कोविड-19 (नोवेल कोरोना वायरस) के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जाने वाले संभावित कदमों पर भी विचार विमर्श किया गया जो कि:

(ए) नए प्रवेशक जिसमें अंतरिम बेल/आपातकालीन पैरोल/फरलों की अवधि समाप्त होने के पश्चात आत्मसमर्पण के लिए वापिस आने वाले समिलित हैं।

(बी) जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ

(सी) राशन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के लिए जेल परिसर में प्रवेश करने वाले अन्य व्यक्ति।

### जेल स्टॉफ के लिए एहतियाती उपाय इत्यादि

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर वे जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ एवं अन्य का ICMR के दिशा निर्देशों के आधार पर रैपिड टेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने सूचित किया कि जेल परिसर में प्रवेश करने से पूर्व जेल स्टॉफ की थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। उन्होंने आगे सूचित किया कि उन्होंने जेल स्टॉफ को आगाह किया है वे आपस में बातचीत करने के साथ -2 कैदियों से बात करते समय मास्क पहने और सामाजिक दूरी का पालन करें। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर पीपीई किट पहनने के लिए भी आगाह किया गया है। महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि अध्यक्ष के द्वारा दिए गए को सुझाव के अनुसार स्टॉफ दो परत सुरक्षा मास्क का प्रयोग कर रहा है और मास्क के साथ -2 वे वाइसर (visor) का भी प्रयोग भी कर रहे हैं।

उन्होने आगे सूचित किया कि दिनांक 27.11.2020 तक **279** जेल स्टॉफ कोविड पॉजिटिव पाया गये। जिसमें से **263** पहले ही ठीक हो चुके हैं। उन्होने अध्यक्ष को अवगत करवाया कि वर्तमान में जेल स्टॉफ के केवल **16** सक्रिय केस हैं जो कि घर में एकांत में हैं।

महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि जब भी कोई जेल स्टॉफ **कोविड-19** पॉजिटिव पाया जाता है उन्हें उनकी डयूटी से छुट्टी दे दी जाती है और उन्हें घर में एकांत में रहने के लिए कहा जाता है। महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि इस प्रकार के सब केसों की contact tracing की जा रही है और वे सब जो इन जेल स्टॉफ के contact में आए थे उन सब को medically screened और टेस्ट किया जा रहा है। महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि उन्होने जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ एवं अन्य का कैदियों से संपर्क कम कर दिया है जिससे के जेल परिसर के अंदर **कोविड-19** के प्रसार को रोका जा सके।

नए प्रवेशकों जिसमें अंतरिम बेल/आपातकालीन पैरोल/फरलों की अवधि समाप्त होने के पश्चात आत्मसमर्पण के लिए वापिस आने वाले समिलित हैं, के लिए उठाए गए एहतियाती उपाय

समिति के सदस्यों ने विचार विमर्श के पश्चात पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों को दोहराया कि नए प्रवेशकों को अलगाव वार्ड में रखना चाहिए जिससे कि वे पहले से ही जेल के अंदर बंद कैदियों से घुलने मिलने से रोका जा सके।

समिति की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि तिहाड़ के जेल न. 1, जेल न.2, जेल न. 4, जेल न. 7 और जेल न. 8/9 मंडोली की जेल न. 15 जिसमें **248** व्यक्तिगत सेल(संलग्न शौचालयों के साथ) हैं, को “अलगाववार्ड” के रूप में 21 वर्ष से अधिक आयु के नए पुरुष कैदियों के लिए बनाया जाए और तिहाड़ की जेल न. 5 को 18–21 वर्ष के बीच की आयु वाले नए कैदियों के लिए अलगाव वार्ड के रूप में बनाया जाए। वहीं नई महिला कैदियों के लिए तिहाड़ की जेल न. 06 को में “अलगाव वार्ड” के रूप में बनाया जाए।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि “अलगाव वार्ड” अब पूरी तरह से भर गए हैं, पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से मंडोली जेल के साथ ही स्थित पुलिस क्वार्टरों के आबंटन की मांग की जाए जिससे कि उक्त फ्लैटों को अस्थाई जेल के रूप में परिवर्तित किया जा सके और 21 वर्ष से अधिक आयु के नए प्रवेशकों को रखने के लिए अलगाव वार्ड के रूप में प्रयोग किया जा सके जहां उन्हें 14 दिन की आरंभिक अवधि के लिए रखा जाएगा।

## अस्थायी जेल : जेल में अतिरिक्त आवास

प्रधान सचिव (गृह) के साथ –2 महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि उन्होने अस्थायी जेल बनाने और उसे अलगाव वार्ड के रूप में प्रयोग करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से 12 टावर के आबंटन के लिए पुख्ता प्रयास किए हैं जिसमें प्रत्येक टावर में 30 फ्लैट हैं। प्रधान सचिव (गृह) समिति को सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की अधिसूचना न. 9/70/2020/HG/2427-2441 दिनांक 31.07.2020 के द्वारा कोविड-19 महामारी को दृष्टि में रखते हुए अगले आदेश तक मंडोली जेल के साथ ही स्थित पुलिस क्वार्टरों को अस्थायी जेल घोषित कर दिया है।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित कियाकि पुलिस आवासीय परिसर, मंडोली में 12 टावर हैं जिसमें से प्रत्येक में 30 फ्लैट हैं। उन्होने बताया कि 12 टावरों में से 4 टावर बी.सी.डी और ई ब्लॉक पूरी तरह से क्रियाशील हैं। यह भी बताया गया कि इन टावरों में उन्होने 223 कैदियों को रखा है जिसे उन्होने अस्थायी जेल में परिवर्तित कर दिया है। उन्होने आगे यह भी बताया कि टावर जी, एच आई, जे, के एवं एल टावर कैदियों को रखने के लिए तैयार है और दो टावर ए और एफ को बाहरी सुरक्षा बलों को रखने के लिए सुरक्षित रखा गया है।

इस तथ्य से अवगत करवाने पर कि अस्थायी जेलों में पहले ही 223 कैदियों को रखा गया है और अन्य को आत्मसमर्पण के पश्चात रखा जाएगा अध्यक्ष ने उपरोक्त अस्थायी जेल में जेल प्राधिकारियों के द्वारा किए गए उनके सुरक्षा उपायों के बारे में पूछा और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कैदियों को इन अस्थायी जेल में रखते समय कोई अप्रिय घटना न हो।

अध्यक्ष की अस्थायी जेल में रहने वाले कैदियों के बचाव और सुरक्षा की चिंता को देखते हुए महानिदेशक (जेल) ने “अस्थायी जेल” में रहने वाले कैदियों के बचाव और सुरक्षा के लिए अपनाए गए एहतियाती उपायों के विषय में अध्यक्ष को अवगत करवाया।

उन्होने आश्वासन दिया कि कैदियों के बचाव और सुरक्षा के लिए एस.ओ.पी. और अन्य प्रोटोकॉल के अनुसार जेल में पालन की जाने वाली आवश्यक सावधानियां “अस्थायी जेल” में रखी गई हैं। उन्होने आगे सूचित किया कि अस्थायी जेल को सील करने के लिए जेल प्रशासन द्वारा पी.डब्ल्यू.डी. से आवश्यक सहयोग लिया गया है जिससे कि अस्थायी जेल के अंदर कैदियों कर अनावश्यक आवाजाही की जांच की जा सके विशेषकर उन फ्लैट्स/अपार्टमेन्ट की बालकनी को सीमित कर दिया गया है जिन्हें अस्थायी जेल में बदला गया है। जैसे कि अस्थायी जेल से कैदियों के भागने की संभावना की भी जांच की गई है और आवश्यक सावधानी बरती जा रही है।

महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि एक बार ये सभी टावर पूर्णतः क्रियाशील हो जाए तो अस्थायी जेल के इन टावरों में लगभग 2000 कैदियों को रख सकते हैं। महानिदेशक (जेल) से यह सूचना प्राप्त करने के पश्चात समिति का यह विचार है कि जेल में नए प्रवेशकों के लिए अलगाव वार्ड बनाने की समस्या काफी हद तक हल हो गई है।

अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का पालन करते हुए विचाराधीन कैदियों/दोषियों के आत्मसमर्पण के अवसर पर उन्हें संबंधित जेल में भेजने से पूर्व अस्थायी जेल में आरंभिक 14 दिन की अवधि के लिए अस्थायी जेल में रखा जाएगा। महानिदेशक (जेल) ने आश्वासन दिया कि इस सुझाव का पालन किया जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि पहले लिए गए निर्णयानुसार नए पुरुष कैदी जिनकी आयु 18 से 21 वर्ष के बीच है और नई महिला कैदियों को तिहाड़ की जेल न. 5 और 6 में तथा मंडोली जेल न. 16 में क्रमशः अलग अलगाववार्ड में रखा जाएगा।

### जेल अस्पताल

अध्यक्ष ने जेल अस्पताल में आक्सीजन से संबंधित मशीनों के प्रयोग के साथ –2 कैदियों के रेपिड एंटीजन टेस्ट संबंध में पूछताछ की। महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि उन्होने आक्सीजन से संबंधित 04 मशीने खरीदी थीं उसके पश्चात दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने आक्सीजन से संबंधित 15 मशीनों की आपूर्ति की। अतएव तिहाड़, मंडोली और रोहिणी जेल परिसर के अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में आक्सीजन से संबंधित मशीने उपलब्ध हैं। महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि ICMR के दिशा निर्देशों के अनुसार कैदियों के रेपिड एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि जेल अस्पतालों में उचित संख्या में आक्सीमीटर और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ–2 आवश्यक दवाइयों और उपकरणों की नियमित रूप से आपूर्ति हो रही है।

### अन्य एहतियाती उपाय

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को आगे उपायों के बारे में अवगत कराया कि कोविड-19 (नोवेल कोरोना वायरस) के प्रकोप को रोकने के लिए जेल स्टॉफ, कैदी, जेल कर्मचारी और अन्य व्यक्ति आवश्यक सावधानी बरत रहे हैं और सामाजिक दूरी के सिद्धांत का गहनतापूर्वक पालन कर रहे हैं। उन्होने अध्यक्ष को इस बात से भी अवगत कराया कि स्नान क्षेत्र, रसोई क्षेत्र, जेल टेलीफोन क्षेत्र को नियमित रूप से साफ और कीटाणुनाशक के द्वारा उचित रूप से सेनेटाइज किया जा रहा है। उन्होने आगे बताया कि जेलों में स्थापित “पब्लिक एड्रेस सिस्टम” के माध्यम से

कैदियों को आवश्यक सावधानियों के बारे में सूचित किया जाता है कि उन्हें “क्या करना चाहिए क्या नहीं”।

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि जेल स्टॉफ और कैदियों की जेल डॉक्टरों के द्वारा नियमित चिकित्सीय जांच की जा रही है और यदि डॉक्टर के द्वारा किसी को सलाह दी गई है तो वह तुरंत जेल अधीक्षक को सूचित करे और यदि वे किसी कैदी में कोविड-19 (नोवेल करोना वायरस) के लक्षण पाते हैं या किसी पर संदेह करते हैं तो उसे ICMR स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी सलाह/दिशानिर्देश के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। उन्होंने अध्यक्ष को आगे सूचित किया कि जेलों में स्वच्छ सकारात्मक व्यवहार के अभ्यास, प्रचार और प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

महानिदेशक (जेल) ने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त उन्होंने कोविड-19 (कोरोना वायरस) के खतरे से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जैसे:

- (ए) सभी बाहरी एजिसियों जिनमें गैर सरकारी संगठन भी सम्मिलित हैं, के दौरा करने पर रोक।
- (बी) कैदियों के वार्ड से बाहर घूमने फिरने पर रोक।
- (सी) कैदियों को रखने वाले क्षेत्रों को और स्टॉफ के आवासीय परिसर को नियमित रूप से साफ और कीटाणुरहित रखना।
- (डी) सभी नए कैदियों को जेल में बंद करने से पहले सीपीआरओ में पूर्व जांच की जाती है।
- (ई) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट, मास्क, दस्ताने, अल्कोहल युक्त हैंड रब और साबुन की खरीद और वितरण।
- (एफ) सभी जेलों में संदिग्ध कोविड-19 (नोवेल कोरोना वायरस) के "**Contact Tracing**" के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन।
- (जी) नए भर्ती कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक स्क्रीनिंग।
- (एच) रसोई/कैंटीन में कर्मियों द्वारा रसोई की स्वच्छता और सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का उचित प्रकार से प्रयोग पर बल।

महानिदेशक (जेल) ने आश्वासन दिया कि जेल प्रशासन इन निर्णयों और सावधानियों का पालन करता रहेगा ताकि जेल परिसर में कोविड-19 (नोवेल कोरोना वायरस) के प्रकोप को रोका जा सके।

समिति महानिदेशक (जेल) के द्वारा उठाए जा रहे कदमों से संतुष्ट है और उन्हें ऐसा निरंतर करते रहने का निर्देश दिया।

#### आइटम नं. 2: जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री और मेडिकल स्टॉफ की स्क्रीनिंग के विषय में उठाए गए कदम

जेल परिसर में कोविड-19 (नोवेल कोरोना वायरस) का प्रवेश जेल स्टॉफ, पैरामिलिट्री स्टॉफ, मेडिकल स्टॉफ और अन्य और उनके माध्यम से होने की संभावना पर विचार करते हुए कैदियों में उसके प्रसार को रोकने के लिए समिति के द्वारा अतिरिक्त उपायों पर विचार-विमर्श किया गया।

अध्यक्ष के द्वारा पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के पालन के संबंध में पूछे जाने पर महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि वे उन निर्देशों का सख्ती से पालन कर रहे हैं और जेल स्टॉफ और अन्य के माध्यम से कोविड-19 (कोरोना वायरस) कैदियों तक पहुंचने के खतरे से निपटने के लिए उन्होंने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि समिति के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर उन्होंने ICMR के दिशा निर्देशों के अनुसार उपरोक्त निर्दिष्ट जेल स्टॉफ के लिए रेपिड टेस्ट का आयोजन किया और आवश्यकतानुसार जेल स्टॉफ का टेस्ट आरंभ कर दिया गया है।

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि जेल स्टॉफके लिए मास्क पहनना अनिवार्य है और कैदियों से बातचीत करते समय सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए आगाह किया गया है।

समिति महानिदेशक (जेल) के द्वारा उठाए जा रहे कदमों से संतुष्ट है और उन्हें ऐसा निरंतर करते रहने का निर्देश दिया। तदानुसार यह हल किया जाता है।

#### आइटम नंबर 3:-जेलों में भीड़ कम करने के लिए पहले अपनाए गए मानदंडों के प्रभाव का जायजा

माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बैच के द्वारा दिनांक 23.03.2020 को पारित आदेश के साथ ही उच्चाधिकार समिति की बैठक दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020 18.04.2020 05.05.2020 18.05.2020, 20.06.2020, 31.07.2020, 30.08.2020 और

**24.10.2020** को अपनाए गए मानदंडों के आधार पर रिहा किये गए बंदियों का व्यौरा समिति के समक्ष रखा गया। पहले अपनाए गए मानदंडों के अनुसार रिहा किए गए कैदियों के अतिरिक्त समिति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के केस शीर्षक **W.P. (Criminal) No.779/2020** के आधार पर व्यक्तिगत बांड पर रिहा किये गए विचाराधीन कैदियों का पुनः अवलोकन किया। जिसके आंकड़े महानिदेशक (जेल) के पत्रांक **PS/ DG(P)/2020/2089** दिनांक 27.11.2020 में उल्लिखित हैं।

समिति ने रिहा किए गए विचाराधीन कैदियों का अवलोकन किया जो इस प्रकार है –

दिनांक 27.11.2020 तक अंतरिम जमानत पर छोड़े गए कैदी	<b>3499</b>
माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा W.P.(Criminal) No.779/2020 में जमानत आदेशों में किए गए संशोधन के आधार पर रिहा किए गए विचाराधीन कैदी	<b>310</b>
आपातकालीन पैरोल पर रिहा किए गए दोषी	<b>1183</b>
सजा में प्राप्त छूट से रिहा हुए दोषी	<b>122</b>
दिनांक 27.11.2020 तक अंतरिम जमानत/ पैरोल/ सजा में प्राप्त छूट से रिहा हुए कुल दोषी	<b>5114</b>

#### अंतरिम जमानत:

समिति के सदस्यों ने स्वयं को उस लक्ष्य का स्मरण करवाया जिसको ध्यान में रखकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केस शीर्षक **"Suo Motu Petition (Civil) No.1/2020 – In Re: Contagion of COVID-19"** के द्वारा समिति का गठन उन कैदियों के श्रेणी/वर्ग पर विचार करने के लिए किया था जिनको अंतरिम जमानत/पैरोल पर छोड़ा जा सकता है। यह केवल अपराध की गंभीरता पर नहीं बल्कि अपराध की प्रकृति और अन्य संबंधित कारकों पर निर्भर करता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस समिति का गठन, महामारी की अभूतपूर्व परिस्थितयों जिसके परिणामस्वरूप लॉकडाउन और न्यायालय के कार्य प्रतिबंधित हो गए थे, के कारण किया गया था। जिससे कि जेलों में भीड़ को कम किया जाए ताकि सामाजिक दूरी के सिद्धांत का पालन हो सके और कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके। समिति के सदस्यों ने दिनांक 13. 04.2020 के बाद के आदेश का स्मरण कराया जिसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने राज्यों को कैदियों को अनिवार्य रूप से रिहा करने का आदेश नहीं दिया है।

समिति के सदस्यों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर यह महसूस किया कि इस समिति का गठन उपरोक्त लक्ष्य को लेकर किया गया था जिसका उद्देश्य केवल जेलों की भीड़ को कम करने का हल ढूँढ़ना और वायरस के प्रसार से बचना था और ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि इन परिस्थितियों में अंतरिम जमानत से लाभ सामाजिक गिरावट के लिए नहीं हो सकता है।

समिति के सदस्यों की यह रॉय है कि यह व्यवस्था केवल अस्थायी आधार पर की गई है और इसका अर्थ कभी भी जमानत के या मान्यता प्राप्त सिद्धांतों/अनुदानों से इनकार के पूरक के रूप में नहीं था। इसके अतिरिक्त ये उपाय तब किए गए जब लॉकडाउन और मौजूदा परिस्थितियों के कारण न्यायालयों का कामकाज प्रतिबंधित था। हालांकि स्थिति अब बदल गई है, इसलिए इन अस्थायी उपायों को सदा के लिए बढ़ाया नहीं जा सकता है।

भारत सरकार के दिनांक 30.09.2020 के आदेश सं. **40-3/2020-DM-I(A)** को ध्यान में रखते हुए अनलॉक 5 के संबंध में है और जो दिनांक 15.10.2020 से प्रभावी है और तदानुसार परिस्थितियों के परिवर्तन और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश सं. **538/RG/DHC/2020** दिनांक 19.10.2020 को ध्यान में रखते हुए, जिसमें सभी न्यायालय जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में कार्य पुनः भौतिक रूप/विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से शुरू हो रहे हैं। इस समिति ने यह निर्णय लिया है कि कि विचाराधीन कैदियों के लिए अंतरिम जमानत की सिफारिशों के मानदंडों को और अधिक लचीला नहीं बनाया जाएगा।

यह स्पष्ट किया गया है कि इस समिति द्वारा अपनी पहले की बैठकों में अपनाए गए मानदंडों के लाभ जो कि पिछली बैठक के अनुसार दिनांक 30.09.2020 तक जारी रहना था, को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है।

समिति के सदस्यों का यहीं विचार है कि सभी न्यायालय यानि माननीय उच्च न्यायालय के साथ –2 अधीनस्थ न्यायालय भी पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं अतः सभी विचाराधीन कैदी न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतन्त्र हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह के आवेदन जब कभी भी दायर किए जाएंगे तो कानूनी सिद्धांतों के आधार पर संबंधित न्यायालयों द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

हालांकि यह पहले ही स्पष्ट किया गया है परंतु फिर दोहराया जाता है कि इस समिति द्वारा दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020, 18.4.2020, 05.05.2020, 18.05.2020, 20.06.2020, 31.07.2020, 30.08.2020 एवं 24.10.2020 की बैठक में अपनाए गए मानदंड विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ने का निर्णय और आज यहां अपनाई गई योजना अन्य विचाराधीन कैदियों के

अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी। जो विचाराधीन कैदी इन श्रेणियों में नहीं आते हैं वे संबंधित न्यायालयों में अंतरिम/नियमित जमानत के लिए विनती कर सकते हैं। ऐसे विचाराधीन कैदियों द्वारा आवेदन दाखिल करने पर संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार मेरिट पर इस पर विचार कर सकते हैं।

### सजा की छूट :

अध्यक्ष के द्वारा पूछे जाने पर महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि दिनांक 28.03.2020 की उच्चाधिकार समिति की सिफारिशों के आधार पर माननीय उपराज्यपाल ने आदेश सं. F.9/63/2020 दिनांक 07.04.2020 के द्वारा पात्र दोषियों को सजा की छूट प्रदान की है। उन्होंने आगे सूचित किया कि कार्यालय आदेश के अनुसार आज तक 72 दोषियों को सजा की छूट पर छोड़ा गया है।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को आगे सूचित किया कि माननीय उपराज्यपाल के आदेश सं. F.9/63/2020/HG/2184 दिनांक 21.07.2020 में दोषियों के छूट के लाभ देने का निर्देश दिया गया है। जो कि 30 सितम्बर, 2020 तक इसके लिए पात्र हो जाएगे। समिति के संज्ञान में लाया गया कि इस नए आदेश के आधार पर आज तक 33 और दोषियों को सजा की छूट पर रिहा किया गया है। अतः आज तक 105 दोषियों को सजा की छूट का लाभ मिला है।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को आगे सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने विशेष सजा की छूट प्रदान करने के लिए पुनः दिनांक 07.04.2020 के आदेश को दिनांक 31.12.2020 तक के आगे बढ़ा दिया गया है। तदानुसार 17 और दोषियों को सजा की छूट पर रिहा किया गया है। अतः दिनांक 27.11.2020 तक 122 दोषियों को सजा की छूट का लाभ मिला है।

अध्यक्ष ने पूर्व की बैठकों में अपनाए गए निर्णयों का पालन और किए गए प्रयासों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, जेल प्रशासन और डीएसएलएसए की सराहना की।

### आइटम नंबर 4:-दिनांक 30.08.2020 की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत बढ़ाने के संबंध में जायजा

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा, ने समिति को सूचित किया कि दिनांक 24.10.2020 की बैठक में दिए गए निर्देशानुसार उन्होंने दिनांक 28.10.2020 को माननीय रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय को पत्र लिखा था।

उक्त पत्र के आधार पर माननीय विशेष पीठ ने ***Writ Petition (Civil) Number***

**3080/2020, titled “Court on its own Motion Vs. Govt. of NCT of Delhi & Anr.”** दिनांक 05.11.2020 के आदेश में जिन 3337 विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत को आगे बढ़ा दिया गया था उनकी अंतरिम जमानत को उनकी पूर्व अंतरिम जमानत समाप्त होने की तारीख से 30 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाए जाने के साथ –2 समिति के दिनांक 24.10.2020 में अभिलिखित मानदंडों के आधार पर विचाराधीन कैदियों (जिसमें 3499 विचाराधीन कैदी सम्मिलित हैं) को प्रदान की गई अंतरिम जमानत की अवधि 05.12.2020 से समाप्त होने जा रही है।

समिति के संज्ञान में लाए कि यदि इस समिति द्वारा निर्धारित विभिन्न मानदंडों के तहत जिन 3499 विचाराधीन कैदियों और 1183 दोषियों को अंतरिम जमानत/आपातकालीन पैरोल दी गई है और उन्हें उसी अवधि के समाप्त होने पर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है तो दिल्ली की जेलों की कुल आबादी 20500 तक पहुंचने की संभावना है जो कि अभूतपूर्व होगी और वर्तमान स्थिति और परिस्थितियों के कारण असहनीय हो सकती है।

उन्होंने यह भी बताया कि आज तक केवल एक अवसर पर दिल्ली की जेलों की अधिकतम आबादी 18,000 तक पहुंची है।

महानिदेशक (जेल) ने इस प्रकार तर्क दिया कि वर्तमान जेलों की जनसंख्या देखते हुए जो कि 16100 है और कोविड-19 को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यह उचित होगा कि उच्चाधिकार समिति के मानदंडों के तहत 3499 विचाराधीन कैदियों और 1183 दोषियों की अंतरिम जमानत/आपातकालीन पैरोल की अवधि को 45 दिनों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

महानिदेशक (जेल) के द्वारा लिखा गया पत्रांक **PS/DG(P)/2020/2090** दिनांक 27.11.2020 का पत्र भी समिति के संज्ञान में लाया गया।

समिति के सदस्यों ने महानिदेशक (जेल) के द्वारा लिखा गया दिनांक 27.11.2020 के पत्र को पढ़ा और महानिदेशक (जेल) द्वारा दिए गए तर्कों विशेषकर महामारी की वर्तमान स्थिति और दिल्ली में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श किया।

इस समिति ने अपनी अंतिम बैठक में दिल्ली में कोविड-19 की उस समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समिति को आशा थी कि स्थिति में सुधार हो जाएगा। हालांकि कोविड-19 की स्थिति ने 360 डिग्री का टर्न ले लिया है।

इस स्थिति में जीवित रहने के लिए समिति ने दिल्ली में दिनांक 01.11.2020 से कल यानि दिनांक 27.11.2020 तक कोविड-19 के अचानक बढ़े सक्रिय केसों पर विचार

किया।

दिल्ली में कोविड-19 के सक्रिय केसों के साथ –2 कोविड-19 के कारण हुई मौतों के आंकड़े इस प्रकार हैं

दिल्ली में कोविड –19 के आंकड़े			
क्रम सं.	दिनांक	सक्रिय केसों की संख्या	मृत्यु
1.	01.11.2020	5664	51
2.	02.11.2020	4001	42
3.	03.11.2020	6724	48
4.	04.11.2020	6842	51
5.	05.11.2020	6715	66
6.	06.11.2020	7178	64
7.	07.11.2020	6953	79
8.	08.11.2020	7745	77
9.	09.11.2020	5023	71
10.	10.11.2020	7830	83
11.	11.11.2020	8593	85
12.	12.11.2020	7053	104
13.	13.11.2020	7802	91
14.	14.11.2020	7340	96
15.	15.11.2020	3235	95
16.	16.11.2020	3797	99
17.	17.11.2020	6396	99
18.	18.11.2020	7486	131
19.	19.11.2020	7546	98
20.	20.11.2020	6608	118
21	21.11.2020	5879	111
22.	22.11.2020	6746	121
23.	23.11.2020	4454	121

24.	24.11.2020	6224	109
25.	25.11.2020	5246	99
26.	26.11.2020	5475	91
27.	27.11.2020	5482	98

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि कोविड –19 की स्थिति इस महीने के दौरान अक्टूबर के मुकाबले अत्यंत खराब हुई है। हालांकि पीक पर दिनांक 11.11.2020 से नए केसों में कुछ सुधार हुआ है और दिनांक 27.11.2020 तक कुल संचयी केसों की संख्या 556744 है और प्रतिदिन सक्रिय केसों की संख्या अभी भी अधिक है।

दिल्ली में कोविड–19 के केसों में आए अचानक उछाल से यह प्रतीत होता है कि अभी यह निश्चित नहीं है कि महामारी की आशंका कब समाप्त होगी। इसको ध्यान में रखते हुए समिति के सदस्यों का यह विचार है इस समिति द्वारा निर्धारित विभिन्न मानदंडों के तहत जिन 3499 विचाराधीन कैदियों और 1183 दोषियों को अंतरिम जमानत/आपातकालीन फैरोल दी गई है यदि इस स्थिति में आगे बढ़ाई नहीं जाती और विचाराधीन कैदियों और दोषियों को इस समय आत्मसमर्पण के लिए कहा जाता है तो यह एक खतरनाक प्रस्ताव होगा क्योंकि हो सकता है कि वे अपने साथ संक्रमण ले आयें। अतः इस समिति का एकमत विचार है कि इस प्रकार का कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता अतः यह निर्णय लिया जाता है कि 3499 विचाराधीन कैदियों को प्रदान की गई अंतरिम जमानत को 45 दिनों के लिए आगे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

डीएसएलएसए के सदस्य सचिव ने समिति को आगे सूचित किया कि माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जिस विशेष पीठ का गठन किया गया था जिसने उच्चाधिकार समिति के मानदंडों के तहत **W.P. (C) 3080/2020** दिनांक 05.11.2020 के आदेश के द्वारा विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत को पहले बढ़ाया गया था वही अब दिनांक 02.12.2020 के लिए सूचीबद्ध है।

समिति की राय है कि इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से एक न्यायिक आदेश की आवश्यकता होगी और तदानुसार सिफारिश की जाएगी। सह स्पष्ट किया जाता है कि ये 3489 विचाराधीन कैदी जिनकी सिफारिश की गई है वे हैं जो कि समिति की पिछली बैठकों में अभिलिखित मानदंडों में से किसी एक में आते हैं इस तथ्य के बावजूद कि अंतरिम जमानत के लिए आवेदन

उनके द्वारा अथवा उनकी ओर से किसी निजी अधिवक्ता अथवा डीएसएलएसए के पैनल अधिवक्ता के द्वारा दायर किया गया था।

सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण को यह निर्देश दिया जाता है कि समिति की इन सिफारिशों को इन कार्यवृत्त (Minutes) की प्रतिलिपि के रूप में माननीय रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

इस समिति की सिफारिशों के आधार पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा इस तरह के किसी भी आदेश के पारित होने की स्थिति में यह स्पष्ट किया जाता है कि जेल प्रशासन ऐसे विचाराधीन कैदी को टेलीफोन के द्वारा उनके पहली अंतरिम जमानत की अवधि के समाप्त होने से पूर्व आगे की 45 दिन की अवधि के लिए सूचित करेगा। महानिदेशक (जेल) ने आश्वासन दिया कि जेल प्रशासन आवश्यक कार्यवाही करेगा और विचाराधीन कैदियों को उनके आत्मसमर्पण की सही तारीख के बारे में सूचित करेगा।

हालांकि यह स्पष्ट है लेकिन फिर भी यह स्पष्ट किया जा रहा है कि इस समिति द्वारा अलग-2 न्यायालयों द्वारा अलग-2 तारीखों में 45 दिन की अवधि के लिए विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत दी गई थी। अंतरिम जमानत की यह अवधि इस समिति के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच द्वारा "**W.P.(C) 3080/2020** शीर्षक **"Court on its own Motion Vs. State"**, आरंभ में दिनांक **09.05.2020** के आदेश द्वारा, जिस तारीख को उनकी अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त हो रही थी, उस तारीख से 45 दिनों के लिए बढ़ाई गई थी और उसी को समय-2 पर दिनांक **22.06.2020, 04.08.2020** और अंत में **18.09.2020** को 45 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। जिसे पिछली बार दिनांक 05.11.2020 के आदेश से 30 दिन की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। इन 3499 विचाराधीन कैदियों को अलग-2 तारीखों पर अंतरिम जमानत दी गई थी। इस तरह उनकी अंतरिम जमानत चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएगी इसलिए उनके आत्मसमर्पण के लिए अलग से तारीखों की आवश्यकता नहीं है।

**आइटम नंबर 5:- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के द्वारा दोषियों को प्रदान की गई आपातकालीन पैरोल को आगे बढ़ाने के संबंध में फीडबैक**

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि समिति के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने दोषियों को 8 सप्ताह के लिए आपातकालीन पैरोल प्रदान की थी। जो कि बाद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के गृह विभाग के आदेश के द्वारा समय समय पर बढ़ाई गई।

समिति ने इसकी पहले की बैठकों में अपनाए गए निर्णयों का अनुपालन करते हुए और दिल्ली

में महामारी की स्थिति पर विचार करते हुए उस समय महानिदेशक (जेल) को उन दोषियों को पहले से ही प्रदान की गई आपातकालीन पैरोल को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से अपेक्षित अनुरोध का निर्देश दिया गया था।

**दिनांक 24.10.2020** की अंतिम बैठक में श्री बी.एस. भल्ला, प्रधान सचिव (गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली समिति के संज्ञान में **F.No.18/191/2015-HG/3263-68** दिनांक **06.10.2020** का आदेश लाए जिसमें महानिदेशक (जेल) के पत्र और समिति के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सभी दोषियों की आपातकालीन पैरोल को आगे 4 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की आदेश सं. **18/191/2015-HG/3554-61 dated 29.10.2020** के द्वारा उन सभी दोषियों की जिनकी आपातकालीन पैरोल की अवधि 28.11.2020 को या उससे पहले समाप्त होने जा रही है, को 4 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।

उपरोक्त आइटम न. 4 में समिति के सदस्यों द्वारा किए गए विचार विमर्श को और वर्तमान जेल की आबादी को को ध्यान में रखते हुए समिति का विचार है कि 1183 दोषियों की, जिनकी आपातकालीन पैरोल जो कि 09.01.2021 को या उससे पहले समाप्त होने जा रही है उसे 6 सप्ताह की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

महानिदेशक (जेल) इस आशय से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का पत्र भेज सकते हैं। महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि इस बैठक की संभावना के कारण उन्होंने विशेष सचिव (गृह) को दिनांक 26.11.2020 को 1183 दोषियों की, जिनकी आपातकालीन पैरोल जो कि 09.01.2021 को या उससे पहले समाप्त होने जा रही है की आपातकालीन पैरोल को 6 सप्ताह की अवधि के लिए आगे बढ़ाने के लिए पहले ही पत्र लिख दिया है।

प्रमुख सचिव (गृह) ने कहा कि वे जल्द से जल्द राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से जारी आदेश / निर्देश प्राप्त करेंगे।

बैठक के कार्यवृत्त का पालन सभी संबंधितों के द्वारा किया जाएगा।

अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त हुई।

---

संदीप गोयल  
महानिदेशक (जेल)

---

श्री बी.एस. भल्ला  
प्रमुख सचिव (गृह)

---

कंवलजीत अरोड़ा  
सदस्य सचिव  
डीएसएलएसए

---

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री हिमा कोहली,  
कार्यकारी अध्यक्ष,डीएसएलएसए

---

यह सत्यापित किया जाता हैं कि दिनांक 28.11.2020 की बैठक के कार्यवृत्त का हिन्दी अनुवाद  
मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

हिन्दी अनुवादक  
डीएसएलएसए